



2026:AHC:65584

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण ज़मानत आवेदन संख्या- 9699 वर्ष 2026

हिमांशु @ छोटे आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य प्रतिपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: सतेंद्र सिंह

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं - 67

माननीय न्यायमूर्ति श्री अरुण कुमार सिंह देशवाल

1. आवेदक के अधिवक्ता श्री सतेंद्र सिंह, राज्य के अपर शासकीय अधिवक्ता श्री रोशन कुमार सिंह को सुना और अभिलेखों का अवलोकन किया।
2. प्रस्तुत ज़मानत आवेदन केस अपराध संख्या-669 वर्ष 2025 में धारा 103(1) बी.एन.एस., थाना-ताजगंज, जिला-आगरा के तहत सुनवाई के लंबित रहने के दौरान आवेदक को ज़मानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर किया गया है।
3. आवेदक के अधिवक्ता का तर्क यह है कि आवेदक का नाम केवल कथित से प्राप्त जानकारी के आधार पर प्राथमिकी में दर्ज किया गया था। हालाँकि, उक्त प्रत्यक्षदर्शियों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि हालांकि घटना से एक दिन पहले आवेदक और मृतक के बीच झगड़ा हुआ था, लेकिन उनमें से किसी ने भी घटना को नहीं देखा। इसका तात्पर्य यह है कि आवेदक ने कथित तौर पर घटना के अगले दिन उनसे कहा था कि वह मृतक को लगी चोट के बारे में किसी को सूचित न करें। आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि आवेदक को केवल खून से सना हुआ कुदाल बरामद करने के आधार पर झूठा फंसाया गया है। यह स्थापित करने के लिए कोई एफएसएल रिपोर्ट नहीं है कि कुदाल पर पाया गया खून मृतक का है। आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि प्रस्तुत मामले में

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



आरोप पत्र दायर किया गया है, इसलिए हिरासत में पूछताछ की कोई आवश्यकता नहीं है। आवेदक कानून का पालन करने वाला नागरिक है और वह 08.10.2025 से जेल में बंद है। यदि उसे जमानत मिल जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और मुकदमे की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

4. तत्स्य विपरीत, अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत के लिए प्रार्थना का पुरजोर विरोध किया है, लेकिन उपरोक्त तथ्यों पर विवाद नहीं कर सका।

5. मामले के संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, पक्षों के अधिवक्ता की प्रस्तुतियाँ और अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्तों की मिलीभगत को ध्यान में रखते हुए और अवर न्यायालयों के समक्ष भीड़भाड़ वाली जेलों और आपराधिक मामलों के भारी लंबित मामलों को ध्यान में रखते हुए साथ ही **कपिल वधावन बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो 2025 एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 3038 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले** के जनादेश पर विचार करते हुए और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मेरी राय है कि आवेदक जमानत पर रिहा किये जाने का हकदार है।

6. उपरोक्त अपराध में शामिल आवेदक- हिमांशु उर्फ छोटे को निम्नलिखित शर्तों के साथ संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए एक व्यक्तिगत बांड और समान राशि में दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए: -

- i. आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यों का खुलासा करने या सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने से रोका जा सके।
- ii. आवेदक किसी भी स्थगन की मांग किए बिना ईमानदारी से परीक्षण/जांच में सहयोग करेगा।
- iii. जमानत पर रिहा होने के बाद आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि या किसी भी अपराध में शामिल नहीं होगा।
- iv. आवेदक अपने द्वारा निष्पादित बांड की शर्तों के अनुसार उपस्थित होगा।



7. उपरोक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन के मामले में, यह ज़मानत रद्द करने का आधार होगा।

8. बांड स्वीकार करने से पहले आवेदक और ज़मानतदार की पहचान, स्थिति और निवास प्रमाण को संबंधित न्यायालय द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए।

9. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को इस आदेश की कंप्यूटर जनित प्रति के आधार पर जारी किया जाएगा, जो उच्च न्यायालय इलाहाबाद की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड की गई है और संबंधित अधिवक्ता द्वारा इस वचन के साथ सत्यापित किया जाएगा कि प्रमाणित प्रति 15 दिनों के भीतर दाखिल की जाएगी।

10. यह भी निर्देश दिया जाता है कि विचारण न्यायालय आवेदक की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित करने के लिए ज़मानत आदेश प्रबंधन प्रणाली (बी.ओ.एम.एस.) के माध्यम से संबंधित जेल को रिहाई का आदेश भेजेगा।

11. कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि वह ज़मानत देने के लिए नीतिगत रणनीति के मामले में शीर्ष न्यायालय के आदेश के अनुपालन में संबंधित जेल अधीक्षक के माध्यम से ई-मेल या ई-जेल पोर्टल के माध्यम से आवेदक को, इन रे: स्वतः संज्ञान रिट याचिका (क्रिल०) संख्या-4 वर्ष 2021 31.01.2023 को तय की गई (2024)10 एस.सी.सी. 685 में रिपोर्ट की गई, इस आदेश की एक प्रति भेजे।

मार्च 30, 2026

एस.सी.

(न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल)